# भारत की कम्युनिस्ट पार्टी(माओवादी)
# COMMUNIST PARTY OF INDIA (MAOIST)
## केन्द्रीय कमेटी

**प्रेस विज्ञप्ती**

30 अप्रैल 2021

# भारत के संसाधनों को ईयू को बेचने और उससे मिलिटरी क्षेत्र में समझौते करने के लिए उद्देश्यित भारत के प्रधान मंत्री के पुर्तगाल कार्यक्रम का विरोध करो!

**विदेश में खासकर ईयू और ब्रिटेन में निवासरत भारतीय क्रांति के प्रिय कामरेडों व मित्रों,**

**लाल सलाम!**

केंद्रीय कमेटी की ओर से मैं आप सभी लोगों और उत्पीड़ित जनता और सर्वहारा वर्ग से अपील करता हूं कि मई 8 को पुर्तगाल के पोर्टो में आयोजित होने वाले ईयू और इंडिया मीट में, कुछ वाणिज्य और मिलिटरी समझौते जो साम्राज्यवादी हितों के मकसद से भारत की जनता को लूटने का मार्ग सुगम करने वाले हैं और पुर्तगाल व ईयू के सर्वहारा वर्ग की जनता के हितों के खिलाफ है, करने के मकसद से भारत के ब्राह्मणीय हिंदुत्व फासीवादी प्रधान मंत्री मोदी के भाग लेने के विरोध में बड़े पैमाने पर प्रतिरोध कार्यक्रम का संचालन करें और इस कार्यक्रम का विरोध करें. फिलहाल मेरा देश दूसरे दौर की कोरोना महामारी के संकट का तीव्र रूप से सामना कर रहा है. कल 24 घंटों के भीतर ही तीन लाख लोगों को संक्रमित होकर उसने सभी पुरानी रिकार्डों को तोड़ दिया. जनता तीव्र घबराहट में है. लेकिन देश के प्रधान मंत्री को इसकी जरा भी चिंता नहीं है और वे नियमित चुनाव कार्यक्रम एवं मेक इन इंडिया कार्यक्रम में बेहद व्यस्त हैं. उपरोक्त बैठक भी उसी का हिस्सा है. भारत में केंद्र और राज्य सरकारें इस महामारी से निपटने सिर्फ प्रचार तक ही सीमित हो रही हैं. सरकारों द्वारा हाल में आविष्कृत कोरोना वैक्सीन बाजार में प्रतियोगितात्मक माल बना दिया गया. जनता और देश के प्रति सरकार के इस रवैये का हमारी पार्टी कड़ा विरोध करती है.

बड़े कॉर्पोरेट घरानों के फायदे के लिए केंद्र सरकार द्वारा लाए गए कृषि कानूनों के विरोध में विगत नवंबर 26 (भारतीय संविधान दिन) से भारत के किसान हड़ताल पर हैं. नोट बंदी और जीएसटी जैसी मोदी की लोक लुभावन एवं घातक आर्थिक नीतियों के चलते बहुत से छोटे और मध्यम वर्गीय व्यापारियों ने अपना व्यापार खोया. इनके व्यापार 2020 के लॉकडाउन से बुरी तरह प्रभावित हो गए. अब वे लॉकडाउन का विरोध कर रहे हैं और उन्होंने इसके विरोध में, खासकर महाराष्ट्र में संघर्ष करने का निर्णय लिया. हिंदुत्व विचारधारा, निजीकरण–कारपोरेटीकरण, अति केंद्रीकरण को बढ़ावा देने वाली नयी राष्ट्रीय शिक्षा नीति का भारत वर्ष में छात्र और प्रगतिशील बुद्धिजीवी कड़ा विरोध कर रहे हैं. देश भर में श्रमिक जनता सरकार की एलपीजी नीतियों और पूंजीवादियों के हितों के लिए श्रमिक कानूनों में किए गए बदलावों का विरोध कर रही है. सीएए और उस तरह के अन्य कानूनों जो भारतीय संविधान के जनानुकूल पहलुओं के विरोधी हैं और पूरी तरह तथाकथित हिंदू बहुसंख्यक लोगों के धर्म पर आधारित हैं, का जनवादी, धर्मनिरपेक्ष और प्रगतिशील तबकें कड़ा विरोध कर रहे हैं. भारत के मूलवासी अपने जल, जंगल, जमीन पर अधिकारों को हासिल करने के लिए पेसा और नया वनाधिकार कानून – 2006 जैसे सरकारी कानूनों के अमल की मांग कर रहे हैं. लेकिन सभी सरकारें उन्हें क्रूर कानूनों में फंसा रही हैं और सजाएं दे रही हैं. हमारी पार्टी – भाकपा (माओवादी) राज्य व केंद्र सरकारों की सभी जन विरोधी नीतियों की कड़ी निंदा करती है. मोदी राज में बड़ी तादाद में जनवादियों, धर्मनिरपेक्ष ताकतों, जनपक्षधर इतिहासकारों, बुद्धिजीवियों, लेखकों, कलाकारों, तार्किकों, अधिवक्ताओं और पत्रकारों की गिरफ्तारी हुई और उनकी आवाज दबाई गई. गौरी लंकेश, गोविंद पंसारे, कलबुर्गी और नरेंद्र दभोलकर जैसे कुछ जन पक्षधर बुद्धिजीवियों की हत्याएं की गईं. भीड़ की हत्याएंसाल दर साल बढ़ रही हैं. भारत की जाति व्यवस्था में दलितों और मुसलमान समुदाय के लोग इनका शिकार हो रहे हैं.

जनता की जायज मांगों को लेकर सभी जनवादियों और जनपक्षधर ताकतों के साथ मिलकर हमारे क्रांतिकारी जन संगठन जन संघर्षों का निर्माण कर रहे हैं. शोषक शासक वर्ग खासकर केंद्र व राज्यों में सत्तारूढ़ प्रतिक्रियवादी हिंदुत्व

ताकतें इसे बर्दास्त नहीं कर पा रही हैं. वे उन पर अर्बन माओवादी की मुहर लगा रही हैं, उनकी आवाज दबा रही हैं और उनका शिकार कर रही हैं. फिलहाल जन संगठनों के दर्जनों नेता सलाखों के पीछे हैं.

आप लोग इस विषय से वाकिफ हैं कि हमारी पार्टी विगत पांच दशकों से भारत देश में क्रांतिकारी आंदोलन का निर्माण कर रही है. पार्टी के नेतृत्व में हमारी जन मुक्ति छापामार सेना सशस्त्र संघर्ष संचालित कर रही है. लेकिन भारत के शासक वर्ग उनके साम्राज्यवादी आकाओं खासकर अमेरिकी साम्राज्यवादियों के सहयोग से हमारी पार्टी और क्रांतिकारी आंदोलन का उन्मूलन करने के लिए कोशिश कर रहे हैं. उन्होंने पुलिस और पैरा मिलिटरी के 6 लाख से अधिक बलों, जो काउंटर इन्सरजेन्सी गुरिल्ला युद्ध में सुशिक्षित हैं, को तैनात किया. आंदोलन को 5 साल में खत्म करने के लक्ष्य से – जनता पर युद्ध के तौर पर ऑपरेशन समाधान 2017 से देश भर में संचालित हो रहा है. खासकर विगत एक वर्ष से उनके ऑपरेशन प्रहार हमलें जारी हैं. हमारी पीएलजीए क्रांतिकारी जनता के साथ मिलकर समर्पित भावना और दृढ़संकल्प के साथ इसका प्रतिरोध कर रही है. हाल ही में उसने जन राज सत्ता यानी क्रांतिकारी जनताना सरकार और क्रांतिकारी आंदोलन को बचाने के मकसद से खूंखार डीआरजी और राज्य और केंद्र के अर्द्ध सैनिक बलों पर कडेनार (नारायणपुर जिला, छत्तीसगढ़), जीरागुडा (बीजापुर जिला, छत्तीसगढ़) और पश्चिम सिंगभूम (झारखंड) में एंबुशों को अंजाम दिया. फासीवादी मोदी राज में 2014 से हमने एक हजार से अधिक तादाद में पार्टी के नेताओं और पीएलजीए के योद्धाओं व क्रांतिकारी जनता को खोया.

भारत के केंद्रीय गृहमंत्री पाखंडी अमित शाह और छत्तीसगढ़ राज्य के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बौखलाहट में क्रांतिकारी जनता के दमन के लिए और अधिक पुलिस बलों को तैनात करने का एक मत से निर्णय लिया. हवाई हमले करने के लिए भी वे बेहद आतुर हैं. इसके पहले ही महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्दव ठाकरे यह कहते हुए कि माओवादी कोविड–19 से भी खतरनाक हैं, गढ़चिरोली के जंगलों में लगातार ऑपरेशंस जारी रखने के लिए सी–60 कमांडों को भड़का रहे हैं. दो दशकों से अधिक वक्त से हमारे क्रांतिकारी आंदोलन के रणनीतिक इलाके अघोषित युद्ध क्षेत्रों में तब्दील हो गए हैं. नरसंहार, महिलाओं के साथ पुलिस बलों के सामूहिक बलात्कार के अलावा वहां की जनता पर अनगिणत पुलिस अत्याचार जारी हैं. क्रांतिकारी आंदोलन को कुचलने के लिए वर्तमान में ऐसी तमाम जन विरोधी गतिविधियों को तेज करने के लिए उन्होंने निर्णय लिया. इसलिए आखिर में और एक बार मैं विदेशों में निवासरत कामरेड्स और भारतीय क्रांति के मित्रों सहित ईयु विशेषकर पुर्तुगाल के सर्वहारा से अपील करता हूं कि वे ईयू द्वारा भारत की अत्यधिक लूट को सुनिश्चित करने के लिए उद्देश्यित भारत के फासीवादी प्रधान मंत्री के पुर्तगाल यात्रा का एकता के साथ जबर्दस्त विरोध–प्रतिरोध करें.

**क्रांतिकारी अभिवादन के साथ,**

**अभय,**

अभय

**प्रवक्ता,**

**केंद्रीय कमेटी,**

**भाकपा (माओवादी)**